

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 712] No. 712] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 21, 2017/श्रावण 30, 1939

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 21, 2017/SRAVANA 30, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2017

सा.का.नि.1038(अ).— केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ) और खंड (ट) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में नियम 2 के उपनियम (1) में, खंड (छख) में उपखंड (iii) में निम्नलिखित पंरतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु बकाया पर इस सीमा को विचार में नहीं लिया जाएगा जब सरकारी अनुदानों, कल्याण प्रसुविधाओं और उपापन के प्रति संदाय, के माध्यम से निक्षेप किया गया है।"।

> [अधिसूचना सं.3/2017/फा. सं. पी 12011/11/2016-ईएस सैल-डीओआर] बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव,

5105 GI/2017 (1)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, आसाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.444 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं.717 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2005, सा.का.नि. सं.389 (अ), तारीख 24 मई, 2007, सा.का.नि. सं.816 (अ), तारीख 12 नवंबर, 2009, सा.का.नि. सं.76 (अ), तारीख 12 फरवरी, 2010, सा.का.नि. सं.508 (अ), तारीख 16 जून, 2010,सा.का.नि. सं.980 (अ), तारीख 16 दिसंबर, 2010, सा.का.नि. सं.481 (अ), तारीख 24 जून, 2011, सा.का.नि. सं.576 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2013, सा.का.नि. सं. 288 (अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015, सा.का.नि. सं. 544 (अ), तारीख 7 जुलाई, 2015, सा.का.नि. सं.633 (अ), तारीख 11 सितंबर, 2015, सा.का.नि. सं. 730(अ), तारीख 22 सितंबर, 2015, सा.का.नि. सं. 882(अ), तारीख 18 नवंबर, 2015, सा.का.नि. सं. 347(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2017 और सा.का.नि. सं. 538(अ), तारीख 1 जून, 2017 को संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2017

- **G.S.R. 1038(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (h), clause (i), clause (j) and clause (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Third Amendment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, in rule 2, in subrule (1), in clause (fb), in the sub-clause (iii), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that this limit on balance shall not be considered while making deposits through government grants, welfare benefits and payment against procurements.".

[Notification No. 3/2017/F.No. P.12011/11/2016-ES Cell-DoR] BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended by number G.S.R. 717 (E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389 (E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R.816 (E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R. 76 (E), dated the 12th February, 2010, number G.S.R. 508 (E), dated the 16th June, 2010, number G.S.R. 980 (E), dated the 16th December, 2010, number G.S.R. 481 (E), dated the 24th June, 2011 and number G.S.R. 576 (E), dated the 27th August, 2013, number G.S.R. 288 (E), dated the 15th April, 2015, number G.S.R. 544 (E), dated the 7th July, 2015, number G.S.R. 693 (E), dated the 11th September, 2015, number G.S.R. 730 (E), dated the 22nd September, 2015, number G.S.R. 882 (E), dated the 18th November, 2015, number G.S.R. 347 (E), dated the 12th April, 2017 and number G.S.R. 538 (E), dated the 1st June, 2017.